भी है और आपको भी, है लेकिन अब आप इस लोभ का सचरण करें । अब मैं जो एक महत्वपूर्ण डिस्कसन होना है, उसकी शुरुआत करता हूं ।

श्री राम नरेश यादव : उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में जो खाद का कारखाना है, वह दो साल से बंद है जिसके कारण वहां के मजदूरों की दशा अत्यंत ही दयनीय हो गयी है । मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सरकार इस फैक्ट्री को चलाने के लिए काम करे ताकि मजदूरों की दशा सुधर सके । उपसभाध्यक्ष महोदय, यह पूर्वांचल का बहुत बड़ा उद्योग है जो कि आज बहुत ही खराब स्थिति में आ गया है । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस उद्योग को चलाने की दिशा में तत्काल कदम उठाए ताकि वहां के मजदूरों की दयनीय स्थिति में कुछ सुधार आए और पूर्वांचल के विकास की दशा में भी एक कदम उठाया जा सके । यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है ।

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, all the parties and groups including the ruling party yesterday decided that discussion on securities scam will be taken up immediately after Question Hour. There will be no other issue—not even Zero Hour. *(Interruptions)* Six hours discussion was decided. *(Interruptions)* The Prime Minister will come at 12.45 P.M. *(Interruptions)*.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Kindly take your seat. I am going to begin.

आज आप छोड़ दीजिए, कल उठा लीजिए

Now, Dr. Murli Manohar Joshi is to raise a discussion on the statement on irregularities and fraudulent transactions in banks and other financial institutions, made by the Minister of Finance in the Rajya Sabha on July 8, 1992.

SHORT DURATION DISCUSSION on irregularities and fraudulent transactions in banks and other financial institutions.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माननीय सदस्यगण, डा. मुरली मनोहर जोशी जी का यह पहला भाषण है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे । अब मैं जोशी जी का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे सदन की यह परंपरा रही है कि बहुत अच्छी चीजें इस सदन में वरिष्ठ सदस्य रखते रहे हैं । जब कोई भी उत्तेजना की बात होती है तो उससे सदन का माहौल गरम होता है । जोशी जी स्वयं भी इस बात का ध्यान रखेंगे जिससे कि दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर ऐसे ही सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करेंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री एच० हनुमनतप्पा) पीठासीन हुए

डा० मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया और आपने मुझे जो सुझाव दिया और संकेत किया कि सदन की गरिमा अनुरूप यहां भाषण और कार्यवाही होनी चाहिए । मैं भी यही मानता था और मानता हूं कि प्रत्येक सदस्य को इस आचरण का पालन करना चाहिए और विशेषकर उन्हें जिन्हें कि पीठासीन अधिकारी होने का अवसर मिलता है, लेकिन मुझे कभी-कभी ऐसा भी दिखायी देता है कि जो लोग पीठासीन अधिकारी के पैनल पर है, वह भी सदन की मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करने में सहयोग करते हैं । मैं समझता हूं कि लोग उसका भी ध्यान रखेंगे ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज की यह परिचर्चा वित्त मंत्री जी द्वारा आर्थिक अनियमितताओं और शेयर बाजार में हुई धोखाधड़ी के बारे में दिए गए बयान से संबंधित है । मैं यह समझता था कि हमारे सम्माननीय वित्त मंत्री जी, जोकि अर्थशास्त्री भी हैं और जो भारत की अर्थ-व्यवस्था के प्रबंध में बहुत वर्षों तक प्रमुख भूमिका का निर्वाह करते रहे हैं, उनके बयान में कुछ ऐसी चीजें होंगी,

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

कुछ ऐसी सूचनाएं होंगी जिससे कि इस समस्या के वास्तविक रूप और गहराई से हम परिचित हो सकेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने जितनी रोशनी डालने की कोशिश की, अंधेरा और ज्यादा बढ़ गया । उन्होंने चीजों को छिपाने की ज्यादा कोशिश की है और बताने की कम जो चीजें आमतौर पर अखबारों में आ गई हैं, जिनके बारे में रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, उसी को सार रूप में रख देना, कोई ऐसी नई चीज नहीं थी कि जिससे हम यह जान सके होते कि सरकार ने इस समस्या के निवारण के लिए क्या किया है, क्या उसका उद्देश्य है, और क्या वह करना चाहती है । इस समस्या के कितने आयाम है, कितने डायमेन्शन्स है, उसके बारे में भी इसमें कुछ पता नहीं चलता ।

महोदय, इसमें यह तो कहा गया है कि बैंकों में प्रतिभूति लेन देनों में पाई गई अनियमितताएं थीं । और, यह भी कहा गया है कि कुछ बेईमान दलालों ने कतिपय बैंक अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके अपने प्रयोजनों के लिए विभिन्न स्तरों से स्थापित नियमों और मार्गदर्शक निर्देशों और विवेकपूर्ण कारोबार प्रथाओं का उल्लंघन किया । यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, कुछ लोगों को पकड़ा गया है और जो बाद में छूट गए है । यह भी कहा गया है कि छापे मारे गए है । यह भी कहा गया है कि अनियमितताओं के लिए जांच की जा रही है । लेकिन यह नहीं कहा गया कि इस घोटाले की गहराई कितनी है, यह कितनी दूर तक देश की अर्थव्यवस्था को स्पर्श करता है, कितनी दूर तक इस देश के आम आदमी के विश्वास को चोट पहुंचाता है, किस गहराई तक रिजर्व बैंक की विफलता के बारे में इंगित करता है, किस संजीदगी के साथ यह हमारे देश के वित्तमंत्री और वित्त मंत्रालय की अक्षमता की ओर संकेत करता है, सारी सरकार के एटीट्यूड के बारे में और सारी समस्या के बारे में जो उनकी जांच सोच है उसके बारे में कहां तक इंगित करता है ? यह घोटाला है । इसमें भ्रष्टाचार है पर इस भ्रष्टाचार की राशि कितनी है ? तीन हजार करोड़ है या साढ़े तीन हजार करोड़ है या पैंतीस हजार करोड़ है या पचास हजार करोड़ है, इसके बारे में कोई जानकारी आपके बयान से नहीं मिलती है । आपका अंदाज क्या है ? कहां तक आप ले जाना चाहते हैं ? क्या आप बताना चाहते हैं ? अब जानकी रमण साहब की रिपोर्ट में 3500 करोड़ है तो आप भी 3500 करोड़ कहते हैं । सरकार क्या सोचती है इसके बारे में ? सरकार का अनुमान क्या है, यह घोटाला कहां तक जाएगा ? इसमें कौन-कौन लोग लिप्त हैं ? यह तो ऊपर से टिप आफ आइस बर्ग दिखाई दे रहा है, हिमखंड का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है । विज्ञान के सिद्धांत में हिमखंड जब पानी में तैरता है तो 1/10 ऊपर होता है और 9/10 नीचे होता है । मुझे ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ 1–10 को ऊपर रखने की कोशिश की है और 9/10 को छिपाने की कोशिश की है ।

महोदय, रिजर्व बैंक की असफलताओं का उल्लेख करने के बावजूद भी मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने रिजर्व बैंक के गर्वनर को अभी तक अपने स्थान पर बनाए रखा है । कैसे रिजर्व बैंक के गर्वनर हैं ? उनके क्या क्रियाकलाप हैं ? किस ढंग से उन्होंने इस सारी व्यवस्था का संचालन किया है ? यह स्वयं अगर आप जानकीरमण की रिपोर्ट को पढ़ें तो उससे पता चल जाएगा । मैं आपका ध्यान इसी रिपोर्ट के पृष्ठ 27 की ओर आकृष्ट करता हूं—

> NHB is a 100 per cent subsidiary of the RBI and was sstablished in July 1988. Until April 1992 it had no Board of Directors but was headed by a full-time Chairman and Managing Director till January 1991 and a part-time Chairmen and Managing Director from April 1991 onwards, added by an Executive Director. Authority for undertaking money market transactions wag given to the dealer Shri C. Ravikumar initially for

call money operations and later for placement of 'very very short-term surplus funds (one/two days) in other money market instruments,"

आगे चल कर कहते हैं,—

"In February 1992, Shri C. Ravt-kumar had prepared a note which stated that 'any change in the investment practices have been done in consultation (formal/informal) with the top management, and that 'it is felt that under the circumstances and also as expressed in the note on yield... the two way trading in assets be regularised and allowed within the overall investment framework of the bank keeping in view low risk, high yield and high profitability'. There is no evidence on the note to show that it has been seen by the higher authorities..."

अब एन०एच०बी०, यह तो हण्ड्रेड परसेंट आपकी सबसिडरी, रिजर्व बैंक सबसिडरी । रिजर्व बैंक के अध्यक्ष को, रिजर्व बैंक के गवर्नर को, अगर उनकी सबसिडरी में कोई उसका अध्यक्ष नहीं है, कोई उसका प्रबन्ध मंडल नहीं है, वहां क्या हो रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है और यह एन०एच०बी० रुपया दे रहा है स्पेकुलेशन के लिए,... बैंक रिसीट्स दे रहा है, पैसा दे रहा है । एन०एच०बी० बना किसलिए था ? क्या इसका उद्देश्य इस देश में सट्टा-खोरी करना था ? एन०एच०बी० का उद्देश्य तमाम आदमियों को मकान बनाने के लिए राहत पहुचाना था । एन०एच०बी० में जो लोग रुपया रखते थे उनका उद्देश्य यही था कि उनको इस माध्यम से अपने सिर के ऊपर छत रखने के लिए कुछ थोड़ा साधन मिले । लेकिन आपने, इस रिजर्व बैंक ने ए न०एच०बी० को इजाजत दे दी कि वह सट्टा बाजार में जा सके, पैसा कमा सके इस गलत रास्ते से रिजर्व बैंक कुछ जानता नहीं है, अचानक ... कि ... छ घोटाला हो रहा है ... र वह भी एन० च०बी० के बारे में बाहर से खबर आई तब । यह कैसी व्यवस्था है ?

एन०एच०बी० के साथ-साथ दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों इस देश में भारी पैमाने पर सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन हुआ । एक साल के अंदर, जो आपकी ही रिपोर्ट बताती कि 9 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ ।

"The total number of transactions reported in respect of Units of the UTI amount to 6,708 with an aggregate value of Rs. 72,760 crores accounting for about 8.03 per cent of the total."

"However, four foreign bankg alone account for transactions of an aggregate value of Rs. 51,633 crores, i.e. 70.96 per cent of the total transactions in Units."

अब भारतीय यूनिट्स के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि क्या विदेशी बैंकों को इस बात की इजाजत है कि वह यूनिट ट्रस्ट का व्यापार कर सके और इंडियन गवर्नमेंट की सिक्युरिटी को या उन सिक्युरिटीस में व्यापार कर सकें ? क्या रिजर्व बैंक ने उनको अनुमति दी है ? 14 महीने के पीरियड में, 1 अप्रैल, 91 से 23 मई, 92 तक, जो कांट्रैक्ट्स एंटर हुए बैंक्स में उनकी संख्या 58 हजार है । 14 महीने में बैंक्स ने 58 हजार ट्रांजक्शन्स किए हैं और 9 लाख करोड़ रुपए का उन सिक्युरिटीज में कुल व्यापार हुआ है । मैं जानना चाहूंगा कि 1990-91 में यह संख्या कितनी थी ? अगर आप पिछले साल की संख्या पर गौर करेंगे तो एक साल में 3, 4 या 5 हजार से ज्यादा ट्रांजक्शन्स नहीं होते थे, लेकिन अगर एक साल में यह संख्या 3 या 5 हजार से बढ़कर 58 हजार ट्रांजक्शन्स हो जाए तो क्या रिजर्व बैंक को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था ? क्या उन्हें यह नहीं देखना चाहिए था कि यह राशियां वह यूनिट्स बार-बार क्यों ट्रांजेक्ट हो रहे हैं ? क्यों बार-बार यूनिट ट्रस्ट भी उन्हीं यूनिट्स को अदला-बदली किया जा रहा है और क्यों यूनिट 1964 के बारे

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

में बाजार के अंदर खरीददारी बढ़ रही है ? क्या वहज थी ? गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अंदर लेन-देन और वह भी विदेशी बैंकों को करने की इजाजत देना, यह मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी भूल थी। आप इस बात पर गौर करें, आपके पास रिपोर्ट की कापी है।

"More than two-thirds of these transactions were entered into by only four foreign banks. The same four foreign banks accounted for over 70 per cent of the transactions in Units."

Seventy per cent of the transactions in Units, given the deposit base of these banks, in hardly three per cent.

केवल 3 प्रतिशत डिपाजिट, जिन लोगों का डिपाजिट बेस था, उन्हें आपने कितनी बड़ी रकम को लेन-देन करने का और कितना बड़ा व्यापार करने की छूट दी। क्या यह भी आई०एम०एफ० की शर्तों में था ?

"... it is obvious that the transactions were not entered into for the purpose of funds management but rather for the arbitrage resulting from purchase and sale.

अब आप देखें कि इस 9 लाख करोड़ का 70 प्रतिशत कितना होगा ? यह भारत की कुल सकल राष्ट्रीय आमदनी है ? 9 लाख करोड़ रुपए का 70 प्रतिशत आप देख लें, भारत की सकल आमदनी देख लें, आपको पता लग जाएगा कि जितना व्यापार इन चार बैंकों ने एक साल में किया है, वह भारत की कुल सकल आमदनी से अधिक है। अगर आप इसका 70 प्रतिशत 6 लाख 30 हजार करोड़ रुपए देखें और .5 प्रतिशत के हिसाब से इस पर ब्रोकेज देखें तो कितनी ब्रोकेज इन बैंक्स को मिली 3 हजार करोड़ रुपऐ से ऊपर। यह इनका मुनाफा है। यह मुनाफा गया?

क्या हवाले के जरिए बाहर चला गया। इस मुनाफे का क्या उपयोग हुआ ? तीन हजार करोड़ रुपए का मुनाफा सिर्फ ब्रोकेज से चार विदेशी बैंक काम कर के ले जायें। यह आपका रिजर्व बैंक क्या कर रहा था ? आप ही का रिजर्व बैंक कहता है। चार ब्रोकर्स हैं—चार विदेशी बैंक। अब जरा आप देखें तो, इसमें स्थिति क्या है ? इसमें सिटी बैंक है, इसमें बैंक आफ अमरीका है, स्टेण्डर्ड चाटर बैंक है और ए०एन०जैड० ग्रीन्डलेज बैंक है। अब इसमें आप यह भी देखेंगे कि सबसे अधिक राशि जिसका व्यापार हुआ है, वह सिटी बैंक से हुआ है। शायद 23 प्रतिशत अकेले इस बैंक ने इसमें हिस्सेदारी ली है। अब यह सिटी बैंक को इतनी हिस्सेदारी कैसे मिली ? यह तमाम प्रतिभूतियों का व्यापार सिटी बैंक के मार्फत कैसे हुआ ? क्या सिटी बैंक को मालूम था कि 1964 की यूनिट का दाम बढ़ने वाला है, उस पर बोनस मिलने वाला है। क्या सिटी बैंक को मालूम था कि सरकार की प्रतिभूतियां मार्च के महीने में जारी होने वाली हैं ? मार्च के महीने में सरकार लोन जारी करे और उसका पता पहले से विदेशी बकों को लगे, मैं समझता हूं कि यह बहुत खतरनाक आयाम है। यह पता कैसे लगा क्या ऐसा तो नहीं है कि सिटी बैंक के अन्दर हमारे देश के बहुत से ब्यूरोक्रेट के रिश्तेदार उसमें काम करते हों ? ऐसा तो नहीं है कि सिटी बैंक के अन्दर हमारे सत्ता पक्ष में बैठे हुए मंत्रियों के नजदीकी लोग, रिश्तेदार काम करते हैं ? क्या ऐसा तो नहीं है कि सिटी बैंक के अन्दर हमारे पुराने ब्यूरोक्रेट के आज भी ऐसे सम्बन्ध हैं कि उनके सम्बन्धियों को, उनकी सन्तानों को उसमें काम करने का अवसर मिलता है। मैं जानना चाहूंगा वित्त मंत्री महोदय से कि वे भारत के उन ब्यूरोक्रेट्स की एक पूरी सूची पेश करें, जो आज सेवा में हैं या सेवा से निवृत्त भी हो गये हैं पिछले 5–7 सालों में उनमें से किस-किस के पुत्र, किसकी पुत्री, किसकी पत्नी, किसके और नजदीकी सम्बन्धी, भाई-भतीजे, साले यह सब उसके अन्दर काम कर रहे हैं। इसकी सूची चाहिए। यह हम जानना चाहेंगे। आज समाचार पत्रों में साफ-साफ कहा जाता

है कि अमुक ब्यूरोक्रेट का पुत्र सिटी बैंक में है, अमुक चेयरमैन का जो पब्लिक सैक्टर का मालिक है उसकी पुत्री सिटी बैंक में है। यह कहा जाता है कि आज भारत सरकार के एक उपक्रम ने, अण्डर-टेकिंग ने एक कमीशन ने स्पेसिफिकली ओ०एन०जी०सी० ने क्या तीन सौ करोड़ रुपए सिटी बैंक में जमा किये हैं? क्यों किये हैं? क्या भारत के बैंकों में वह राशि नहीं जानी चाहिए? क्या रिजर्व बैंक ने निगाह रखी कि भारतीय बैंकों का व्यापार खिसककर विदेशी बैंकों के पास जा रहा है? एक तरफ तो प्रधान मंत्री जी कहते हैं और आपके तमाम मित्र कहते हैं जबकि हम भारत की अपनी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। लेकिन मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था को तो सुदृढ़ नहीं किया गया लेकिन चार विदेशी बैंकों को तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक सिर्फ ब्रोकेज में, दलाली में ले जाने की इजाजत दी गयी। उसके बाद भी रिजर्व बैंक क्या करता रहा यह मेरी समझ में नहीं आता? क्या रिजर्व बैंक का काम सिर्फ भारत के पैसे को, भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे को विदेश में भेजना है और इन तीन हजार करोड़ रुपए का हुआ क्या? क्या हवाले के जरिए इसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और प्रभाव नहीं डाला अब यह सब तो आपकी रिपोर्ट से जाहिर है।

मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं जो रिपोर्ट में कही गई है कि जितने भी नौ लाख करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका लगभग 30 प्रतिशत मैच नहीं करता, रिकंसाइल नहीं करता। अब यह अगर हालात है तो वे कहते हैं कि :

Numter of transactions which have not matched is tabulated below:

Standard Chartered Bank . . . . . •	-23.18%
Citibank	16.37%
Bank of America	14-45%
State Bank of India	9.29%
UCO Bank	6.62%
ANZ Grindlays Bank . . . . - -	.6.12%
Andhra Bank	4.52%
Canara Bank	3.72%

अब अगर यह रिकंसाइल नहीं करता तो यह तीस हजार करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा। हम लोगों ने छोटी सी बात कही थी कि आप आयकर की सीमा को बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दीजिए। तो हमारे वित्त मंत्री साहब को उस पर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ग्यारह सौ करोड़ रुपए का नुकसान हो जायेगा, मैं कहां से लाऊंगा तीन हजार करोड़ रुपए, साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए तो बैंक घोटाले में आपकी जानकीरमन समिति की अन्तरिम रिपोर्ट कहती है। तीस हजार करोड़ रुपए रिकंसाइल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा अभी कितने और हजार करोड़ रुपए के घोटाला का पता नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप देश की अर्थ व्यवस्था की तरफ ध्यान देते और यहां के लोगों को राहत पहुंचाने की बात करते तो शायद देश का अधिके भला होता। मेरे ख्याल में रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ ही साथ आपने भी पूरे तौर पर अनदेखा किया है अपनी जिम्मेदारी को। आपका मंत्रालय इससे बच नहीं सकता, आप स्वयं इससे बच नहीं सका। आप एक अर्थशास्त्री रहे हैं। आप भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 15–20 सालों में महत्वपूर्ण

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

भूमिका निभाते रहे हैं और अनेक पदों पर रहे हैं । इसलिये अगर कोई दूसरा वित्त मंत्री होता तो मैं समझता कि उसको शायद बैंकिंग प्रणाली की बारिकियों को समझने में केठिनाई होगी और अगर पूरे तथ्य उसके सामने न रखे जायें तो शायद उसे पता न लग पाये । लेकिन आपसे तो यह आशा नहीं थी । हम तो यह जानते थे कि आपने यहां कहा था कि आप भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जायेंगे । आर्थिक दृष्टि से देश में बड़ी भारी प्रगति होगी । आर्थिक दृष्टि से तो प्रगति नहीं हुई लेकिन बैंक घोटालों ने जरूर हमारे सामने आपकी अर्थव्यवस्था का एक नया परिप्रेक्ष्य सामने रख दिया है, आपकी नीतियों का पूरा परिप्रेक्ष्य हमारे सामने रख दिया है ।

अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज अर्थव्यवस्था की तारीफ की जा रही है । पिछले साल में स्टाक मार्केट में बड़ा भारी उछाला आया । अब यह उछाला स्टाक मार्केट में अचानक आया । इंडस्ट्रियल ग्रोथ से इसका कोई संबंध नहीं था । अगर देश में उत्पादन बढ़ा होता तब तो हम यह जानते कि लोग उद्योगों में निवेश करने के लिये दौड़ रहे हैं लेकिन औद्योगिक विकास और औद्योगिक उत्पादन तो शेयर मार्केट से मेल नहीं खाता है, मैं ऐसी कम्पनियों को जानता हूं जिनके शेयर पहले दो और चार रुपये में बिकते थे और वे ढाई सौ रुपये, तीन सौ रुपये तक पहुंच गये । जो कम्पनियां बी०आई०एफ०आर० में थीं उनके दाम पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गये यानी जो कम्पनियां सिक हो गई थीं, बीमार हो गई थीं, उनके शेयरों में भी उछाला आया ।

मैं जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी से क्या रिजर्व बैंक ने, आपने, आप के बैंकिंग डिवीजन ने इस बारे में निगाह रखी कि शेयर मार्केट में इतना उछाला क्यों आ रहा है ? मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता । वे उपलब्ध हैं । आपके पास भी है और सारे देश के पास हैं लेकिन अगर इतना बड़ा उछाला शेयर मार्केट में आता है तो उसकी क्या वजह है ? आपने शायद यह वजह बताई थी कि हमारी नयी अर्थव्यवस्था से, नयी अर्थ नीति से देश के अन्दर बड़ा भारी बूम आया है । बूम तो नहीं था, बैलूनिंग जरूर थी । मैं कहता हूं कि

It is not booming but ballooning

हवा भरी हुई थी उसमें, वह खोखला था और बहुत तेजी से उड़ रहा था । उसे हरशद मेहता ने एक कैंची से काट दिया और आपकी अर्थव्यवस्था हवा में उड़ गई और आप जमीन पर रह गये ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह कैसे हो गया कि एक साल में 17000 करोड़ रुपये स्टेट बैंक ने एक जुलाई, 1991 से 6 अप्रैल 1992 तक हरशद मेहता के द्वारा इन्वैस्ट कराए हैं । हरशद मेहता एकदम से 17000 करोड़ रुपये स्टेट बैंक से लेकर इन्वैस्ट करे ? इनको किसका पैट्रोनेज था ? आपका ? किसका था ? आपके किस सहयोगी का था ? देश के किस बड़े राजनीतिज्ञ का वरद हस्त इनके ऊपर था ? इंटरव्यू पर इंटरव्यू छपे हैं । महाराष्ट्र टाइम्स का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था जिसमें एक बैंक जिसको ले लिया गया, उसके अधिकारी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया ? मालूम हुआ साहब का ऊपर से हुक्म था । किसका हुक्म था । साहब का हुक्म था । साहब कौन है ? यह नहीं जानता, वह परदे के पीछे है । जब वह आदमी पकड़ा गया और उससे पूछा गया कि तुम यह क्यों कर रहे थे ? तब उसने यह सब बताया ।

नकली रसीदें बनाई जा रही थीं । बैंक रिसीट्स नकली, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिटस नकली, शेयर्स नकली । आपकी अपनी जानकीरमन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि बैंकों की तरफ से नकली रसीदें दी गई । फेयरग्रोथ कम्पनी तो यह काम कर रही थी बराबर लेकिन अगर यूनिट ट्रस्ट की रसीदें,

सर्टिफिकेट्स नकली हों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नकली हो तो क्या होगा ? इस देश के आदमी के विश्वास पर आपने चोट पहुंचाई है । उसका विश्वास इस देश की निवेश व्यवस्था से हट जायेगा । कौन आयेगा फिर यूनिट ट्रस्ट की यूनिट्स खरीदने के लिये, सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा लगाने के लिये अगर आप यह स्वीकार करते हैं कि नकली और जाली सिक्योरिटीज दी जा रही हैं । वह लोग दे रहे थे जिनको आपका वरद हस्त था । चार दलाल मिलकर इस देश को लूटते रहें, नकली, जाली सिक्योरिटीज देते रहें, रिजर्व बैंक सोता रहे । वित्त मंत्रालय सोता रहे, आप की निगाह उधर न हो तो मैं जानना चाहता हूं कि इस की जिम्मेदारी किसके ऊपर है ? क्या सिर्फ बैंक के बाबू पर है, या सिर्फ बैंक के मैनेजर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि ऐसी बैंक रसीदें जिनके बारे में उस के पास कोई पैसा नहीं है, जिसके विरुद्ध जमा करने के लिए सैक्यूरिटी नहीं है, उनके ऊपर वह हजारों करोड़ों रुपया धड़ दे दे ? कैसे कैसे काम कर रहा था आपका बैंक आफ कैरेड । आपने उधर से कह दिया कि हमने उसको लिक्विडेट कर दिया है . . .

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Sir, it is going to be one o'clock now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): It is his maiden speech, you see. Yes, Mr. Joshi, you continue. . . *(Interruptions')* .. .

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: After the Prime Minister speaks, there will be nothing to speak on ... *(Interruptions)* ...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, this is his maid^a .speech. Let him continue.

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): That is why I am not disturbing him... *(Interruptions)...*

DR. MURU MANOHAR JOSHI: Many people have tried to disturb m» earlier... . *(Interruptions) ...*

बैंक आफ कैरेड को जरा देखें । उसका शेयर कैपीटल था 45 लाख रुपया और रिजर्व था उसके पास 2.72 करोड़ और डिपाजिट था 70 करोड़ । कुल ऐसेट्स थे 89 करोड़ और बैंक रिसीट्स सैकड़ों करोड़ । शेयर कैपिटल 45 लाख ऐसेट्स 89 करोड़ और बैंक रिसीट्स जाली, फ्रोडुलेंट जिनक बरखिलाफ कोई पैसा नहीं है, कोई रुपया नहीं है, कोई सैक्यूरिटी नहीं है वह हैं सैकड़ों करोड़ की । मैट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक को देखें । यह वन ब्रांच बैंक है जिसकी शाखा कहां है बंबई में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी । पामधुनी में है किसी संकरी गली में, जायेंगे तो किसी एक कोने में ये महान कोआपरेटिव बैंक मिलेगा जिसका शेयर कैपिटल है 6.42 करोड़, डिपाजिट्स हैं 4.38 करोड़, बैंक रिसीट्स हैं 1944 करोड़ । एक कमरे में यह बैंक है । बंबई में है । रिजर्व बैंक भी बंबई में है । वित्त मंत्री जी भी बहुत दिनों बंबई में रहे हैं । अगर यह हालत है बंबई के बैंकों की और रिजर्व बैंक की तो भगवान ही बचाए । बैंकों के अंदर क्या हो रहा है, घोटाले किस तरीके से होते हैं, कितनी देर तक होते रहते हैं, यह मुख्य सवाल है । हर्षद मेहता साहब जो इस चीज से जुड़े हुए हैं, अखबारों में आया है कि इसी साल वह फाइनेंस मिनिस्ट्री में लाए गए । उन्होंने भाषण दिया । उन्होंने कहा कि यह क्यों आप आई.एम.एफ. से कर्जा लेते हैं । मैं आपको रास्ता बताता हूं । मैं ऐसा रास्ता बताता हूं कि विदेशी पैसा दौड़ा चला आएगा हिन्दुस्तान की शेयर मार्केट में । प्लानिंग कमीशन के एक सदस्य जो आजकल पब्लिक सैक्टर के शेयरों को प्राइवेटाइज करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वह उनके साथ थे । बताया गया कि क्या लाजवाब नुस्खा है । आप आजमाकर देख लीजिए । यहां लगातार विदेशी निवेश होने लगेगा

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

लेकिन एक ब्रोकरेज में फारेन बैंकों को 4 हजार करोड़ रुपए की दलाली चली गई। अगर यही नुस्खे आपको आजमाने हैं तो भगवान के वास्ते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस से पहले की देश की जनता आपको कहे कि आप अपने स्थान से हटें, मैं कहना चाहूंगा कि आप इस जिम्मेदारी को लें, डिरिलिक्शन आफ ड्यूटी की जिम्मेदारी दिखाते हुए अपना स्थान छोड़ दें। मैं समझता हूं कि यह आपके हित में भी है। इस सरकार के हित में भी है और देश के हित में भी है...

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): He must go... *(Interrup-tinos..*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Pleas$_e$ do not interrupt... (Interruptions) .. .Please do not interrupt... *{Interruptions)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : सिर्फ इसी में देश की भलाई है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please do not interrupt, . . *{Interruptions) ,..*

डा० मुरली मनोहर जोशी : बैंक्स अगर इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं तो उन पर पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का नियंत्रण क्यों नहीं? पब्लिक एकाउंट्स कमेटी बैंकों के बारे में कोई देख-रेख नहीं कर सकती। क्यों? क्रेडिट पर कंट्रोल किसका हो इस मुल्क में? यह क्रेडिट जो बैंकों में जाती है, जो साख जाती है किसी एक आदमी की नहीं होती है। देश का आदमी अपना पेट काट कर पैसा जमा करता है। पहले कहा जा रहा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया कि यह प्राइयोरिटी सेक्टर में पैसा नहीं भेजते, देश के गरीब आदमियों के इन्वेस्टमेंट में बाधा पहुंचती है, बहुत से बड़े लोग इसमें से फंड को साइफन कर लेते हैं अपने-अपने व्यापार में, बैंकों पर सोशल कंट्रोल होना चाहिए, यह बात मानकर इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन आज इन बैंकों ने पिछले 20--25 सालों में हालात पैदा कर दिए हैं उन हालात में क्या प्राइयोरिटी सैक्टर में वह पैसा दे रहे हैं? क्या हमारी बैंकिंग का पैसा जो विदेशों में जा रहा है, 4--4 बैंक मिलकर 3 हजार करोड़ ले जाए, यह क्या इस देश का प्राइयोरिटी सेक्टर है? क्या इस देश के गरीब आदमी, हैंडलूम वाले, कोई ब्रासवेयर वाला, कोई गरीब किसान, मोची, धोबी को उस बैंक का पैसा लेने का हक नहीं हैं? क्या सिर्फ दलाल ही बैंकिंग करेंगे? क्या ट्रांजेक्शन और हथफेरी करके पैसा कमायेंगे और विदेशों को भेजेंगे? क्या बैंकों की यही भूमिका रह गई? क्या रिजर्व बैंक इस भूमिका से सहमत है? क्या यह सदन इस भूमिका से सहमत है? क्या प्रधान मंत्री जी बैंकों की इस भूमिका से सहमत हैं? क्या बैंकों को इसलिए राष्ट्रीयकृत किया गया था? आज यह कहा जा रहा है कि सिस्टम फेल्योर है। ठीक है सिस्टम में कुछ दोष थे और हम उसके निराकरण के लिए बार-बार कहते रहे हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा फेल्योर है उन लोगों का जो प्रबन्ध कर रहे हैं, जो वहां बैठे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है इस बात की कि इस बैंकिंग प्रणाली की, इसके उपयोग की ठीक दिशा भारत के आम आदमी तक पहुंचे। मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर निवेश में इसी तरह से कमी आयेगी तो भारत के विकास कार्यक्रमों का क्या होगा अगर विदेशी बैंक इतना व्यापार करेंगे कि जो भारत की एक वर्ष की सकल आमदनी के बराबर होगा तो इस देश का क्या बनेगा? यह कुछ सवाल है जो इस घटना से हमारे सामने उठकर आ गये हैं।

कुछ और भी सवाल हैं जिनको आपको देखना है। मिस्टर मेहता ने जिन लोगों को और उनके माध्यम से जो लोग इसमें लाभान्वित हुए जो इसमें शामिल थे उन लोगों ने किस-किस ट्रस्ट को पैसा दिये? इस बात को देखा जाए कि जो लोग बेनिफिशरी थे उनके एकाउंट से पैसे कहां-कहां गये, किस-किस चेरिटेबल ट्रस्ट को गये? अखबारों में खबर है, मैं नहीं जानता कितनी सच है। उनमें से कुछ लोगों ने जो इस शेयर घोटाले में शामिल थे राजीव गांधी फांउडेशन में पैसे दिये। अगर सच है तो इसकी जांच कराये। अगर ऐसे लोगों से पैसा लिया गया है तो मैं

समझता हूं वह देश के हित में नहीं होगा, फांउडेशन के हित में नहीं होगा और जिन उद्देश्यों के लिए फांउडेशन बना है उसके हित में भी नहीं होगा। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

सरकारी कूपन रेट्स कब बढे इसकी जानकारी विदेशी बैंकों को कैसे मिली? आप अपनी प्रतिभूतियां किस इन्टरेस्ट पर जारी करने वाले हैं यह एडवांस में कैसे पता लगा? कुछ अखबारों में खबर है कि आर.बी.आई. के आफिशियल्स ने यह बात स्वीकार की कि लीक हुई है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार सिटी बैंक को मिला है और सिटी बैंक के बारे में आमतौर पर यह समझा जाता है कि उसमें हमारे बहुत से ब्योरोक्रेट्स के घर वाले काम कर रहे हैं। हो सकता है योग्यता से गये हों, मैं उनकी योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जब वहां है तो उनके माध्यम से सूचना मिल सकती है, उनके माध्यम से सूचना जा सकती हैं। अगर यह सच है जैसा मैंने कहा ओ.एन.जी.सी. के महाप्रबन्धक की एक संतान वहीं काम करती है और उसके माध्यम से 300 करोड़ रुपये सिटी बैंक में जमा हुए हैं। अगर इसी तरह से और सूचनाएं भी सिटी बैंक को मिलती हैं तो यह रहस्य खुल जाता है कि केवल अकेले सिटी बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों का 23 परसेंट से अधिक कारोबार किया। यह गम्भीर बात है। इस सब बातों पर जो आपका कल का प्रतिवेदन था, स्टेटमेंट था वह चुप था। मुझे बहुत हैरत हुई कि इसमें विदेशों के बैंकों के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया जबकि इस घाटाले का बड़ा बेनिफिशरी, जिनको लाभ मिला है वह विदेशी बैंक है। वित्त मंत्री जी, आपके इस वक्तव्य से मैं ही नहीं, देश की जनता भी बहुत निराश है। यह एक ऐसा वक्तव्य है जिसमें कोई ईमानदारी नहीं हैं। यह एक ऐसा वक्तव्य है जिसके अन्दर कोई नैतिक जिम्दारी न भी नहीं जोड़ी गई है। मैं चाहूंगा कि जितना बड़ा डायमेन्शन, जितना बड़ा आयाम, इस घोटाले का है उसके लिए एक जोयन्ट पार्लियामेंटरी कमेटी की स्थापना की जाए जो इसकी पूरी गहराई से जांच करे और उस कमेटी को बैंकिंग चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स और कानूनी सलाहकारों की सुविधा लेने का हक हो क्योंकि यह बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि यह मामला देश की अर्थ व्यवस्था से संबंधित है, देश की आर्थिक सम्प्रभुता से संबंधित है, देश के विकास से संबंधित है, देश के आम आदमी से संबंधित है, उसके जीवन से संबंधित है। हमारे देश में जिस भरोसे पर आज तक कारोबार होता रहा, बैंकिंग प्रणाली पर आम आदमी का जो भरोसा था, उस भरोसे पर जो गहरी चोट पहुंची है, उसका सवाल है। आम आदमी के विश्वास पर बड़ा आघात पहुंचा है। प्रधान मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं और जब वे इस संबंध में कुछ टिप्पणी करने जा रहे हैं तो वे इस जौयन्ट पार्लियामेंटरी कमेटी की बात को स्वीकार करें और वित्त मंत्री जी को और रिजर्व बैंक के गवर्नर को अपने-अपने स्थानों पर न रखा जाए तो यह देश के हित में होगा, उनके हित में होगा और देश की अर्थ-व्यवस्था के हित में भी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Now, hon. Prime Minister will make a *suo moto* statement. As agreed yesterday, no clarifications will be asked for.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: If the JPC is announced, Shri M. M. Joshi should agree to participate in it, and not boycott it.

STATEMENT BY THE PRIME MINISTER

Appointment of a Joint Parliamentary Committee

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Sir, The events that have unfolded in the last few months in the financial sector of the country have caused grave anxiety to me and the country at large. The ramifications of this matter have to be thoroughly probed and effective measures taken *so* that *the* basic integrity of the financial institutions of the country is not jeopardised and the new economic initiatives taken by the Government *to* strengthen and accelerate the economic growth are in no way inhi-